कृपया प्रकाशनार्थ **15 फरवरी 2014**

पूर्व रेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व भाजपा नेता श्री.राम नाईक ने 15 फरवरी 2014 को पत्रकार परिषद में जारी किया वक्तव्य

अंतरिम रेल बजट में संसदीय नियम व परंपरा का भंग : राम नाईक

मुंबई, शनिवार : ''रेल मंत्री श्री. मल्लिकार्जुन खर्गे जब सदन में रेल बजट पेश कर रहे थे तब चार मंत्रीयों ने शोरगुल कर के जो उधम मचाया वह शर्मनाक था ही, मगर उससे भी गंभीर हरकत स्वयं रेल मंत्री ने की है. लेखानुदान - अंतरिम रेल बजट पेश करते समय उन्होने संसदीय नियम तथा परंपरा भंग कर दी है'', ऐसी आलोचना पूर्व रेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व भाजपा नेता श्री. राम नाईक ने आज मुंबई में पत्रकार परिषद में को संबोधित करते हुए की.

लेखानुदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए श्री. राम नाईक ने कहा, ''जब आम चुनाव नजदीक होते हैं तब पुरा बजट पेश करने के बजाय लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है. अप्रैल से शुरु होने वाले नये वित्तिय वर्ष के पहले 2-4 महिनों के विनियोग के लिए लेखानुदानद्वारा संसद से अनुमति ली जाती है. इसके बारे में स्पष्ट नियम तथा संकेत है, जिनके अनुसार लेखानुदान में कोई भी 'नयी सेवा' या योजना सम्मिलित नही की जाती.'' किंतु रेल मंत्री ने इस समय लेखानुदान पेश करते समय इस परंपरा को भंग कर दिया है. लेखानुदान संसद में पेश करने से पहले मंत्री परिषद उसे अपनी मान्यता देती है. इसका साफ मतलब यह है कि इस नियमभंग में अकेले रेल मंत्री नहीं तो प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ - साथ संपूर्ण मंत्री परिषद भी शामिल है, ऐसी आलोचना भी श्री. नाईक ने की. ''मेरे इस मत को संसदीय कार्यपद्धति के विशेषज्ञ व लोकसभा के पूर्व महासचिव श्री. सुभाष कश्यप जी ने भी पुष्टि की है'', ऐसा भी श्री. नाईक ने कहा.

..2..

रेल मंत्री श्री. खर्गे के लेखानुदान - अंतरिम रेल बजट में 'नयी सेवाएं' इस शीर्षक के अंतर्गत 17 प्रिमियम गाडियां, 38 एक्सप्रेस गाडियां, 10 पैसेंजर गाडियां, 7 मेमु-डेमु गाडियां तथा 6 विस्तारीत गाडियां घोषित की गयी है. साथ ही साथ 19 नये रेल मार्गों का व पाच दोहरे मार्गों का सर्वेक्षण कराने की घोषणा भी है. यह सभी घोषणाएं नियमों तथा संसदीय परंपरा का उल्लंघन करनेवाली है. आनेवाले लोकसभा चुनाव पर नजर रख कर यह घोषणाएं की गयी हैं. इस बात की जितनी आलोचना की जाए वह कम है'', ऐसा श्री. नाईक ने कहा.

''संसदीय परंपरा के अनुसार लेखानुदान में पिछले वर्ष के बजट के कार्यान्वयन की जानकारी दी जाती है. किंतु इस लेखानुदान में तो मुंबई उपनगरी रेल सेवा का जिक्र ही नही है. निजी-सरकारी सहयोग से चर्चगेट-विरार उन्नत रेल मार्ग जैसे प्रकल्पों के लिए रु .एक लाख करोड पूंजि का अंदाजा पिछले बजट में व्यक्त किया गया था. इस के बारे में भी इस लेखानुदान में कोई जानकारी नही है, इतनाही नही तो पिछले वर्ष माल व यात्री किराए के लिए 'रेल टेरीफ प्राधिकरण' बनाने की घोषणा की थी उस पर अंमल क्यों नही हुआ इसका भी कोई स्पष्टीकरण नही किया गया है'', ऐसी आलोचना श्री. नाईक ने की.

रेल मंत्री के साथ-साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार ने भी जनता को गुमराह किया है, ऐसा श्री. नाईक का मानना है. 'पुणे मेट्रो को रेल मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में मान्यता दी है' ऐसा इन दोनों ने भी कहा है, किंतु रेल मंत्री के अभिभाषण में इसका जिक्र ही नही है. ''आनेवाले चुनावों पर नजर रख कर सस्ती लोकप्रियता पाने की यह कोशिश है'', ऐसा भी श्री. नाईक ने अंत में कहा.

(कार्यालय मंत्री)